Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

25 सितम्बर 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में 5,100 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,100 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा किया। ये पहल बुनियादी ढाँचे के विकास, आर्थिक सुधारों और सांस्कृतिक संरक्षण पर केंद्रित हैं, जिनका उद्देश्य पूर्वोत्तर में सतत विकास लाना है।

- **ईटानगर में 3,700 करोड़ रुपये की लागत वाली दो प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। हेओ जलविद्युत परियोजना (240 मेगावाट) और टाटो-I जलविद्युत परियोजना (186 मेगावाट) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में सहायक होंगी।**

- **तवांग कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखी गई। 9,820 फीट से अधिक की ऊँचाई पर स्थित यह केंद्र 1,500 प्रतिनिधियों के लिए जगह उपलब्ध कराएगा और पर्यटन एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा।**

- **विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कुल 1,290 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिनमें बेहतर सड़क नेटवर्क, जल आपूर्ति और चिकित्सा सुविधाएं, साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए नए आवास शामिल हैं।**

Key Points:-

(i) PM मोदी ने कर प्रणाली को सरल बनाने और सुधारों के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, स्थानीय स्वदेशी उत्पादों के लिए समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए GST(वस्तु एवं सेवा कर) 2.0 सुधार और GST बचत उत्सव का शुभारंभ किया।

(ii) उदयपुर में पुनर्विकसित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया गया, जिसकी परियोजना लागत 54 करोड़ रुपये है।

(iii) प्रसाद (तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान) योजना के तहत इस परियोजना में तीर्थयात्रा के अनुभव को बढ़ाने के लिए नए रास्ते और तीन मंजिला परिसर शामिल हैं।

2. CAG रिपोर्ट 2022-23: 16 राज्यों ने राजस्व अधिशेष दर्ज किया; उत्तर प्रदेश 37,263 करोड़ रुपये के साथ सबसे आगे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने अपनी पहली "राज्य वित्त 2022-23" रिपोर्ट जारी की है, जो भारत के 28 राज्यों की वित्तीय स्थिति का एक दशक लंबा व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट

में एक महत्वपूर्ण राजकोषीय बदलाव पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें 16 राज्यों ने राजस्व अधिशेष की सूचना दी है, जो घाटे के पिछले रुझानों से एक बदलाव दर्शाता है।

• उत्तर प्रदेश वित्त वर्ष 2022-23 में 37,263 करोड़ रुपये के राजस्व अधिशेष के साथ देश में अग्रणी है, जो गुजरात के 19,865 करोड़ रुपये और ओडिशा के 19,456 करोड़ रुपये से आगे है।

• उत्तर प्रदेश के बाद, महत्वपूर्ण अधिशेष वाले अन्य राज्यों में झारखंड (₹13,564 करोड़), कर्नाटक (₹13,496 करोड़), छत्तीसगढ़ (₹8,592 करोड़), तेलंगाना (₹5,944 करोड़), उत्तराखंड (₹5,310 करोड़), मध्य प्रदेश (₹4,091 करोड़) और गोवा (₹2,399 करोड़) शामिल हैं।

Key Points:-

(i) रिपोर्ट में कहा गया है कि 16 राज्यों ने राजस्व अधिशेष हासिल किया है, जो 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राजकोषीय जिम्मेदारी और समेकन पथ के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य 2022-23 के दौरान शून्य-राजस्व घाटा या राजस्व अधिशेष हासिल करना है।

(ii) 31 मार्च, 2023 तक, कुल राज्य ऋण ₹59.60 लाख करोड़ था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का लगभग 22.17% था, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) लक्ष्य 20% से अधिक था।

(iii) सकारात्मक रुझान के बावजूद, 12 राज्यों ने राजस्व घाटा दर्ज किया, जिसमें आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक घाटा दर्ज किया गया, जो कुछ क्षेत्रों में चल रही राजकोषीय चुनौतियों को उजागर करता है।

3. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 51वें CPCB स्थापना दिवस की अध्यक्षता की और प्रमुख पर्यावरण निगरानी पहलों का शुभारंभ किया।

22 सितंबर 2025 को, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने नई दिल्ली के परिवेश भवन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के 51वें स्थापना दिवस की अध्यक्षता की, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे, तकनीकी उन्नयन और नियामक सुधारों पर प्रकाश डाला गया।

• CPCB ने नई दिल्ली में एक नए मुख्यालय और पुणे व शिलांग में उन्नत क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। पुणे की प्रयोगशाला 70 पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कर सकती है, जबकि शिलांग की प्रयोगशाला 62 मानकों की निगरानी कर सकती है, जिससे बहु-राज्य पर्यावरणीय आकलन में सहायता मिलती है।

• उन्नत SAMEER 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन, जो एंड्रॉइड और एप्पल आईओएस पर उपलब्ध है, वास्तविक समय वायु गुणवत्ता निगरानी में नागरिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए बेहतर इंटरफेस, व्यक्तिगत अलर्ट और स्थान-आधारित सेवाएं प्रदान करता है।

Key Points:-

(i) CPCB ने प्रदूषित नदी खंडों पर 2025 तकनीकी रिपोर्ट और भारत में मीठे पानी के बेन्थिक मैक्रोइनवर्टेब्रेट्स का उपयोग करके जल निकाय प्रदूषण की पहचान करने पर एक मैनुअल जारी

किया, जिसमें प्रदूषण निगरानी के लिए वैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

(ii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और एजेंसियों को मज़बूत बनाने के लिए, सीपीसीबी ने व्यवहार परिवर्तन हेतु सामाजिक विज्ञान को प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत किया है। इसके अतिरिक्त, संगठनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 13 नए पेशेवरों की भर्ती की गई।

(iii) CPCB ने जन विश्वास अधिनियम, 2023 और पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025 पर प्रकाश डाला, जो कुछ प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण करके अनुपालन को सरल बनाते हैं और पर्यावरण लेखा परीक्षा के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करते हैं।

4. जनजातीय मामलों के मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र भारत ने 'आदि कर्मयोगी अभियान' के तहत आदि युवा फेलोशिप और आदि कर्मयोगी स्वयंसेवक कार्यक्रम लॉन्च किया।

22 सितंबर 2025 को, जनजातीय मामलों के मंत्रालय (MOTA) ने भारत में संयुक्त राष्ट्र (UN) के साथ साझेदारी में, 'आदि कर्मयोगी अभियान' के तहत आदि युवा फैलोशिप और आदि कर्मयोगी स्वयंसेवक कार्यक्रम शुरू किया, जिसे दुनिया के सबसे बड़े आदिवासी जमीनी स्तर के नेतृत्व आंदोलन के रूप में देखा गया, जिसका उद्देश्य आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाना और सामुदायिक स्तर के नेतृत्व को मजबूत करना है।

- **संयुक्त राष्ट्र भारत द्वारा समर्थित, आदि युवा फेलोशिप एक 12 महीने का भुगतान किया जाने वाला कार्यक्रम है, जिसे संरचित शिक्षा, मार्गदर्शन और कैरियर विकास के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।**

- **पहले बैच में 16 आदिवासी युवा फेलो शामिल होंगे, जिन्हें राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों में नियुक्त किया जाएगा। यह कार्यक्रम शासन, नीति कार्यान्वयन और सामुदायिक विकास पहलों का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है।**

- **यह फेलोशिप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0), राष्ट्रीय शिक्षुता कार्यक्रम योजना (NAPS) और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) सहित राष्ट्रीय पहलों के साथ संरेखित है, जिससे आदिवासी युवाओं के लिए कौशल विकास, करियर विकास और रोजगार के अवसरों को एकीकृत किया जा सके।**

Key Points:-

(i) संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) द्वारा समर्थित आदि कर्मयोगी स्वयंसेवक कार्यक्रम ने दो महीने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान के 13 जिलों में 82 स्वयंसेवकों को तैनात किया है।

(ii) इन स्वयंसेवकों को विलेज विजन 2030 की योजना बनाने में सहायता करने, जागरूकता अभियान चलाने, आउटरीच को सुविधाजनक बनाने तथा सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने का कार्य सौंपा गया है।

5. कर्नाटक ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का "LEAP" कार्यक्रम शुरू किया।

सितंबर 2025 में, कर्नाटक सरकार ने राज्य के स्टार्टअप और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ "LEAP (उभरती और त्वरित प्रगति में नेतृत्व)" कार्यक्रम शुरू किया, जिससे यह भारत में राज्य द्वारा संचालित सबसे बड़ी पहलों में से एक बन गया।

- **LEAP कार्यक्रम गहन तकनीकी स्टार्टअप, अनुसंधान-संचालित नवाचार और उद्यमशीलता उपक्रमों को समर्थन देने पर केंद्रित होगा, जिसका उद्देश्य कर्नाटक को प्रौद्योगिकी-संचालित विकास में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना है।**

- **इस पहल का नेतृत्व कर्नाटक सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (ITBT) कर रहा है, जिसकी सीधी निगरानी मुख्यमंत्री और ITBT मंत्री कर रहे हैं।**

Key Points:-

(i) 1,000 करोड़ रुपये के इस फंड का उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), जैव प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, अर्धचालक और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे उभरते स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग, उद्यम सहायता, इनक्यूबेशन सुविधाएं और अनुदान प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

(ii) लीप का उद्देश्य शिक्षा जगत, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देना भी है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्टार्टअप्स को कर्नाटक से वैश्विक स्तर पर विस्तार करने के लिए मार्गदर्शन, बुनियादी ढांचा और नीतिगत समर्थन प्राप्त हो।

INTERNATIONAL

1. 2025 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन (CSAR) समावेशी मानव विकास के लिए इक्विटी-आधारित STI पर परिणाम दस्तावेज़ के साथ संपन्न हुआ।

दक्षिण अफ्रीका G20 प्रेसीडेंसी के तहत, 21 सितंबर 2025 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन (CSAR) का 2025 संस्करण, "समावेशी मानव विकास और वैश्विक स्थिरता के लिए इक्विटी-आधारित विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI)" पर परिणाम दस्तावेज़ को अपनाने के साथ संपन्न हुआ।

- **2025 CSAR का आयोजन विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार विभाग (DSTI) और दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय नवाचार सलाहकार परिषद (NACI) द्वारा किया गया था। इस पहल की संकल्पना सबसे पहले 2023 में भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय (OPSA) द्वारा की गई थी। 2024 संस्करण का आयोजन OPSA और**

UNESCO द्वारा पेरिस, फ्रांस में संयुक्त रूप से किया गया था।

- **भारत का प्रतिनिधित्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) प्रो. अजय कुमार सूद, वैज्ञानिक सचिव डॉ. परविंदर मैनी और मुख्य नीति सलाहकार डॉ. बी. छगुन बाशा ने किया। सभी जी-20 सदस्यों, अतिथि देशों और आधिकारिक ज्ञान भागीदार UNESCO के प्रतिनिधियों ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।**

- **गोलमेज चर्चा तीन विषयों पर केंद्रित थी: सतत विकास लक्ष्य कार्यान्वयन और न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन के लिए एक वैश्विक STI एजेंडा विकसित करना, एक खुली और न्यायसंगत ज्ञान प्रणाली बनाना, और अफ्रीका और विकासशील देशों में क्षमता निर्माण के लिए G20 STI पहलों का लाभ उठाना।**

Key Points:-

(i) अजय सूद ने डेटा प्रतिनिधित्व और कम्प्यूटेशनल क्षमता में वैश्विक AI असमानताओं पर प्रकाश डाला और पहुँच को लोकतांत्रिक बनाने के लिए सहयोगात्मक ढाँचों का आह्वान किया। भारत के वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS), I-STEM, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप (RuTAG), और RuTAGe स्मार्ट विलेज सेंटर (RSVC) को समावेशी सहयोग के लिए स्केलेबल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया।

(ii) CSAR 2025 ने अपना परिणाम वक्तव्य अपनाया, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि, प्रदूषण और ऊर्जा परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय STI सहयोग को बढ़ाने की सिफारिश की गई।

(iii) 22 सितंबर 2025 को, प्रो. सूद ने "सामाजिक प्रभाव और सार्वजनिक नीति के लिए AI" विषय पर यूनेस्को के मोस्ट फोरम 2025 मंत्रिस्तरीय पैनल में भाग लिया। भारत-यूरोपीय संघ प्रौद्योगिकी एवं व्यापार परिषद (TTC) के अंतर्गत क्वांटम प्रौद्योगिकियों, AI, बिग डेटा और STI साझेदारी में सहयोग को मज़बूत करने पर यूके, इटली और यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं।

BANKING & FINANCE

1. RBI ने अनियमित ऋण प्रथाओं के लिए दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण रद्द कर दिया।

22 सितंबर 2025 को, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डिजिटल ऋण संचालन में उल्लंघनों के बाद, दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) का पंजीकरण प्रमाणन (CoR) रद्द कर दिया। पंजीकरण रद्द होने के बाद, कंपनी अब NBFC व्यवसाय नहीं कर सकेगी।

- **कंपनी द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग, विशेष रूप से डिजिटल ऋण गतिविधियों में आचार संहिता के संबंध में RBI के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण कंपनी का CoR रद्द कर दिया गया।**

- **उल्लंघनों ने परिचालन के कई पहलुओं को प्रभावित किया, जिसमें ग्राहकों की खोज, उचित परिश्रम, ऋण वितरण, सेवा और वसूली शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप मानक NBFC प्रथाओं का अनुपालन नहीं हुआ।**

• अनियमित ऋण प्रक्रियाओं ने अपने ग्राहक को जानिए (KYC) सत्यापन को भी बाधित किया, जिससे वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में विनियामक और परिचालन संबंधी चुनौतियां पैदा हुईं।

Key Points:-

कंपनी का डिजिटल ऋण परिचालन किनकैश ऐप, डोलोन ऐप (ज़ेस्ट टॉप वन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड) और ज़ेस्टकैश ऐप (कंपनी का इन-हाउस ऐप) सहित कई ऐप्स पर निर्भर था, जो अनियमितताओं में शामिल थे।

2. क्वांट म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला इक्विटी लॉन्ग-शॉर्ट स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च किया।

17 सितंबर 2025 को, क्वांट मनी मैनेजर्स लिमिटेड (QMML) द्वारा प्रबंधित क्वांट म्यूचुअल फंड (MF) ने भारत का पहला इक्विटी लॉन्ग-शॉर्ट स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड (SIF) 'QSIF इक्विटी लॉन्ग-शॉर्ट फंड' लॉन्च किया, जो निवेशकों को बढ़ते और गिरते दोनों बाजारों के लिए उन्नत रणनीतियों तक पहुंच प्रदान करता है।

• QSIF इक्विटी लॉन्ग-शॉर्ट फंड एक ओपन-एंडेड फंड है जो कंपनी के आकार पर प्रतिबंध के बिना सूचीबद्ध इक्विटी और संबंधित उपकरणों में निवेश करता है।

• यह तेजी और मंदी दोनों बाजार प्रवृत्तियों का लाभ उठाने के लिए लचीली रणनीति का उपयोग करता है और जोखिम प्रबंधन और रिटर्न बढ़ाने के लिए सीमित शॉर्ट पोजीशन के लिए डेरिवेटिव का उपयोग करता है।

Key Points:-

(i) न्यू फंड ऑफर (NFO) 17 सितंबर 2025 से 1 अक्टूबर 2025 तक खुला है। न्यूनतम निवेश राशि 10 लाख रुपये है, जो परिष्कृत इक्विटी रणनीतियों में रुचि रखने वाले उच्च-निवल-मूल्य वाले निवेशकों को लक्षित करता है।

(ii) इस फंड के प्रदर्शन को निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स के आधार पर बेंचमार्क किया जाएगा। इसका प्रबंधन अनुभवी पेशेवरों द्वारा किया जाता है: संदीप टंडन, लोकेश गर्ग, समीर काटे, अंकित पांडे और संजीव शर्मा।

(iii) QSIF इक्विटी लॉन्ग-शॉर्ट फंड SIF श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसे हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा पेश किया गया है, जो निवेशकों को परिष्कृत फंड संरचनाओं के लिए नियामक अनुमोदन के साथ उन्नत निवेश रणनीतियों तक पहुंचने की अनुमति देता है।

3. बैंक ऑफ बड़ौदा ने भारत का पहला eRUPI P2P डिजिटल उपहार सुविधा लॉन्च की।

सितंबर 2025 में, बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने अपने बॉब पे UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) ऐप पर उद्योग में पहली बार eRUPI पर्सन-टू-पर्सन (P2P) डिजिटल गिफ्टिंग सुविधा शुरू की, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के eRUPI सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इस सुविधा के ज़रिए ग्राहक उद्देश्य-विशिष्ट प्रीपेड डिजिटल वाउचर भेज सकते हैं, जो भारत के डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- **eRUPI P2P डिजिटल वाउचर 1 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के मूल्य के जारी किए जा सकते हैं। उपयोगकर्ता असीमित संख्या में वाउचर जनरेट कर सकते हैं, जो कि प्रचलित दैनिक UPI लेनदेन सीमा के अधीन है, जिससे छोटी या बड़ी राशि के उपहार देने की सुविधा मिलती है।**

- **वाउचर किसी भी UPI-सक्षम व्यापारी के पास, कई प्लेटफ़ॉर्म पर, आसानी से भुनाए जा सकते हैं, जिससे इनका उपयोग सहजता से हो सके। यह सुविधा प्राप्तकर्ताओं को निर्दिष्ट श्रेणी में वस्तुओं या सेवाओं के लिए सीधे वाउचर भुनाने की अनुमति देती है।**

- **प्रत्येक वाउचर अहस्तांतरणीय है, और यदि इसकी वैधता अवधि के भीतर इसे भुनाया नहीं जाता है, तो राशि स्वचालित रूप से प्रेषक के खाते में वापस कर दी जाती है, जिससे सुरक्षित और जोखिम मुक्त लेनदेन सुनिश्चित होता है।**

Key Points:-

(i) हालांकि उपयोगकर्ता असीमित वाउचर जारी कर सकते हैं, लेकिन वे दैनिक UPI लेनदेन सीमा के अधीन रहेंगे। शुरुआत में, ये वाउचर खाद्य श्रेणी के लिए उपलब्ध हैं, और चरणबद्ध तरीके से अन्य सेवाओं तक भी इनका विस्तार करने की योजना है, जिससे P2P डिजिटल उपहारों का दायरा व्यापक होगा।

(ii) यह नवाचार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) अपनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है और ई-रुपी के उपयोग को व्यवसाय-से-उपभोक्ता (B2C) से व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) लेनदेन तक विस्तारित करता है, जिससे भारत का डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचा मजबूत होता है।

ECONOMY & BUSINESS

1. श्रम ब्यूरो ने कृषि और ग्रामीण श्रम के लिए अखिल भारतीय सीपीआई और मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए।

सितंबर 2025 में, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (MoL&E) के अंतर्गत श्रम ब्यूरो ने अगस्त 2025 के लिए कृषि श्रम (AL) और ग्रामीण श्रम (RL) के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) जारी किया, जिसका आधार वर्ष 2019=100 था। यह आँकड़े 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के 787 नमूना गाँवों से एकत्र किए गए थे।

- **कृषि श्रम (AL) के लिए CPI में 0.76% की वृद्धि हुई, जो जुलाई 2025 के 135.32 से बढ़कर अगस्त 2025 में 136.34 हो गया। ग्रामीण श्रम (RL) के लिए, यह 0.69% बढ़ा, जो 135.66 से बढ़कर 136.60 हो गया, जो महीने-दर-महीने मध्यम मूल्य वृद्धि को दर्शाता है।**

- **अगस्त 2025 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाद्य सूचकांक बढ़कर 137.07 हो गया, जो जुलाई से 1.39**

अंक अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, यह 1.29 अंकों की वृद्धि के साथ 137.38 हो गया, जो महीने के दौरान खाद्य कीमतों में मामूली वृद्धि दर्शाता है।

Key Points:-

(i) वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर अगस्त 2025 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1.07% और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1.26% पर कम रही, जो ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में सीमित समग्र मूल्य दबाव का संकेत देती है।

(ii) खाद्य मुद्रास्फीति में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए -0.55% और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए -0.28% रही, जो पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में खाद्य कीमतों में मामूली गिरावट दर्शाती है।

2. GRSE ने हाइब्रिड बहुउद्देशीय जहाजों के लिए जर्मन फर्म के साथ 62.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया।

सितंबर 2025 में, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) ने चार हाइब्रिड मल्टी-पर्पस वेसल्स (MPVSs) के निर्माण के लिए कार्स्टन रेहडर शिफ्समाकलर अंड रीडरेई GmbH एंड कंपनी, हैम्बर्ग, जर्मनी के साथ 62.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, साथ ही दो अतिरिक्त प्रणोदन जहाजों के प्रावधान के साथ, GRSE के अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक जहाज निर्माण पदचिह्न को मजबूत किया।

- **इस समझौते पर कमांडर (cdr) शांतनु बोस (सेवानिवृत्त), निदेशक (जहाज निर्माण), GRSE, और थॉमस रेहडर, प्रबंध निदेशक, कार्स्टन रेहडर शिफ्समाकलर अंड रीडरेई ने हस्ताक्षर किए, जिससे भारतीय शिपयार्ड और जर्मन कंपनी के बीच सहयोग को औपचारिक रूप दिया गया।**

- **GRSE ने अप्रैल 2025 में कोरल 7500 DWT MPV श्रृंखला के लिए स्टील कटिंग शुरू की, जो वाणिज्यिक पोत खंड में इसका पहला प्रमुख अंतरराष्ट्रीय निर्यात ऑर्डर है।**

- **बहुउद्देशीय पोत कार्यक्रम जून 2024 में चार पोतों के प्रारंभिक अनुबंध के साथ शुरू हुआ, इसके बाद सितंबर 2024, दिसंबर 2024 और मार्च 2025 में अतिरिक्त ऑर्डर मिले, जिससे कुल ऑर्डर आठ पोतों का हो गया।**

Key Points:-

(i) ये जहाज 120 मीटर लंबे और 17 मीटर चौड़े हैं, जिनमें बैटरी-सहायता प्राप्त हाइब्रिड प्रणोदन, बेहतर ईंधन दक्षता और लचीली कार्गो हैंडलिंग प्रणाली है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

(ii) एक उल्लेखनीय डिजाइन विशेषता यह है कि जहाज़ में डेक पर कई बड़े पवन टरबाइन ब्लेडों को ले जाने की क्षमता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की उभरती हुई रसद आवश्यकताओं को पूरा करती है।

(iii) यह सौदा GRSE द्वारा कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 7,500 DWT MPV के चल रहे निर्माण पर आधारित है, जो इसकी वाणिज्यिक निर्यात क्षमताओं को मजबूत करता है और कंपनी को वैश्विक बाजारों के लिए हाइब्रिड, ईंधन-कुशल और पर्यावरण के अनुकूल जहाजों में एक प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. PESB ने कोल इंडिया लिमिटेड के अगले CMD के रूप में बी साईराम की सिफारिश की।

सितंबर 2025 में, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (PESB) पैनल ने कोयला मंत्रालय के अंतर्गत एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU), कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के अगले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) के रूप में बी साईराम की सिफारिश की। वह पोलावरापु मल्लिकार्जुन (प्रधानमंत्री) प्रसाद का स्थान लेंगे, जो 31 अक्टूबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। इस नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) से अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है।

- **बी साईराम के पास कोयला क्षेत्र में 34 वर्षों से अधिक का अनुभव है, जिसमें खदान योजना और विस्तार, संचालन, सतत खनन, रसद, डिजिटलीकरण और नियामक मामलों में विशेषज्ञता शामिल है, जो उन्हें CIL में शीर्ष नेतृत्व की भूमिका के लिए उपयुक्त बनाता है।**

Key Points:-

(i) मार्च 2024 से, वे नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) के CMD के रूप में कार्यरत हैं और CIL की एक प्रमुख सहायक कंपनी में व्यापक नेतृत्व अनुभव प्राप्त कर रहे हैं।

(ii) अपनी वर्तमान भूमिका से पहले, बी. साईराम सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में निदेशक (तकनीकी) और कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) में कार्यकारी निदेशक (ED) के रूप में कार्यरत थे और तकनीकी एवं परिचालन प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

(iii) PESB पैनल की सिफारिश के बाद, कोल इंडिया लिमिटेड के CMD के रूप में उनकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) से अंतिम मंजूरी मिलने तक लंबित है।

AWARDS

1. 69वां बैलन डी'ओर 2025: उस्मान डेम्बेले और ऐताना बोनमाटी ने शीर्ष सम्मान जीता।

22 सितंबर 2025 को, बैलोन डी'ओर (2025) पुरस्कार समारोह का 69वां संस्करण पेरिस, फ्रांस के थिएटर डू चैटलेट में आयोजित किया गया, जिसमें अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों के साथ-साथ पुरुष और महिला फुटबॉल में विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों का सम्मान किया गया।

- **पेरिस सेंट-जर्मेन (PSG) के फॉरवर्ड ओस्मान डेम्बेले ने 2025 पुरुष बैलन डी'ओर जीता, रेमंड कोपा (1958), मिशेल प्लाटिनी (1983-85), जीन-पियरे पापिन (1991), जिनेदिन जिदान (1998) और करीम बेंजेमा (2022) के बाद यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले छठे फ्रांसीसी खिलाड़ी बन गए।**

• महिला फुटबॉल में, बार्सिलोना और स्पेन की मिडफील्डर ऐताना बोनमाटी ने लगातार तीसरे वर्ष (2023-2025) महिला बैलन डी'ओर जीता, जिससे वह मिशेल प्लाटिनी (1983-85) और लियोनेल मेस्सी (2009-12) के बाद तीन बार यह उपलब्धि हासिल करने वाली इतिहास की तीसरी फुटबॉलर बन गईं।

Key Points:-

(i) इस वर्ष की कोपा ट्रॉफी में बार्सिलोना के लामिने यामल दो बार यह पुरस्कार जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने, जबकि बार्सिलोना फेमिनी की विकी लोपेज ने पहली महिला कोपा ट्रॉफी जीती।

(ii) सुकरात पुरस्कार ज़ाना फाउंडेशन (स्पेन) को प्रदान किया गया, जिसकी स्थापना लुइस एनरिक ने अपनी बेटी की स्मृति में जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारियों से पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए की थी।

(iii) इसके अतिरिक्त, पेरिस सेंट-जर्मेन (PSG) और आर्सेनल को 2025 के दौरान उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए क्रमशः पुरुष और महिला क्लब ऑफ द ईयर नामित किया गया।

SUMMITS & CONFERENCE / COMMITTEES & MEETINGS

1. CSIR-NISCPR ने संयुक्त राष्ट्र विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 में लिंग-समावेशी नवाचार का प्रदर्शन किया।

सितंबर 2025 में, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान (CSIR-NISCPR) ने न्यूयॉर्क, अमेरिका में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (SSUNGA80) के दौरान विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 में वर्चुअल रूप से भाग लिया, जिसमें विज्ञान-संचालित नवाचार और समानता में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

• CSIR-NISCPR द्वारा आयोजित सत्र का विषय था "विज्ञान में महिलाएं और लड़कियां: लिंग-समावेशी नवाचार को बढ़ावा देना, लिंग समानता और बाधाओं को तोड़ना", जिसमें सीएसआईआर को एक केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किया गया।

• CSIR-NISCPR ने अपने व्यापक दृष्टिकोण "CSIR फॉर 5C: कनेक्ट, कोलैबोरेट, कन्वर्ज एंड कन्वर्ट (5C) फॉर ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट" के अंतर्गत "लैंगिक-समावेशी नवाचार को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता और बाधाओं को तोड़ना - सीएसआईआर केस स्टडी" शीर्षक से एक महत्वपूर्ण सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में विज्ञान में अनुसंधान-आधारित समावेशिता पर ज़ोर दिया गया।

• इस सत्र की अध्यक्षता CSIR की उत्कृष्ट वैज्ञानिक डॉ. रंजना अग्रवाल ने की। इसमें वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र में लैंगिक संतुलन को बढ़ावा देने पर केंद्रित शोध प्रस्तुतियाँ, नीतिगत चर्चाएँ और केस स्टडीज़ शामिल थीं।

Key Points:-

(i) चर्चाएं विशिष्ट SDGs , विशेष रूप से SDG 5 (लैंगिक समानता), SDG 8 (सभ्य कार्य और आर्थिक विकास), SDG 10 (कम असमानता) और SDG 17 (लक्ष्यों के लिए साझेदारी) के साथ संरेखित थीं, जो वैश्विक प्रतिबद्धताओं में योगदान देने में CSIR की भूमिका को दर्शाती हैं।

(ii) शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र में "बदलती दुनिया के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM)" शीर्षक से एक पैनल चर्चा हुई। इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार डॉ. अखिलेश गुप्ता ने की।

(iii) शिखर सम्मेलन में STEM में महिलाओं की भागीदारी में लगातार चुनौतियों को रेखांकित किया गया, जिसमें कहा गया कि वैश्विक स्तर पर STEM क्षेत्रों में केवल 35% पेशेवर महिलाएं हैं, जिससे दुनिया भर में समावेशिता और समान अवसरों को बढ़ाने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल मिलता है।

IMPORTANT DAYS

1. विश्व गुलाब दिवस 2025: कैंसर रोगियों के सम्मान और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 22 सितंबर को मनाया जाता है।

विश्व गुलाब दिवस (WRD), जो प्रतिवर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है, कैंसर रोगियों, जीवित बचे लोगों और देखभाल करने वालों के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिन आशा, करुणा और कैंसर की रोकथाम, शीघ्र पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है।

- **विश्व गुलाब दिवस 2025 कैंसर रोगियों और देखभाल करने वालों को सहायता प्रदान करने तथा रोकथाम, शीघ्र पहचान और उपचार रणनीतियों के बारे में जागरूकता फैलाने पर केंद्रित है।**
- **यह दिन दुर्लभ रक्त कैंसर से पीड़ित 12 वर्षीय कनाडाई लड़की मेलिंडा रोज़ की स्मृति में मनाया जाता है, जिनके साहस और लेखन ने 1996 में उनके निधन से पहले कैंसर के बारे में वैश्विक जागरूकता को प्रेरित किया था।**
- **वैश्विक स्तर पर, कैंसर एक प्रमुख स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है, जिसके 2025 तक 20 मिलियन नए मामले सामने आने तथा 9.7 मिलियन लोगों की मृत्यु होने का अनुमान है। फेफड़ों का कैंसर पुरुषों में तथा स्तन कैंसर महिलाओं में सबसे आम है।**

Key Points:-

(i) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) वैश्विक कैंसर के बोझ को कम करने और स्वास्थ्य देखभाल असमानताओं को दूर करने के लिए कैंसर की रोकथाम, जांच, उपचार और उपशामक देखभाल में निवेश बढ़ाने का आग्रह करता है।

(ii) भारत में, ICMR-राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (ICMR-NCRP) ने 2023 में लगभग 1.5 मिलियन नए कैंसर मामलों की सूचना दी, जिसके 2025 तक 1.57 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।

(iii) उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में कैंसर के मामले सबसे अधिक हैं, जो बढ़ती राष्ट्रीय कैंसर चुनौती को उजागर करता है।

2. विश्व गैंडा दिवस 2025: गैंडों के संरक्षण को मज़बूत करने के लिए 22 सितंबर को वैश्विक स्तर पर मनाया गया।

विश्व गैंडा दिवस हर साल 22 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि पाँच शेष गैंडा प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और तत्काल संरक्षण प्रयासों पर प्रकाश डाला जा सके। यह दिन गैंडों को अवैध शिकार और आवास के नुकसान जैसे खतरों से बचाने की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।

- **विश्व गैंडा दिवस की शुरुआत 2010 में WWF (वर्ल्डवाइड फंड फॉर नेचर) दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी और आधिकारिक तौर पर 2011 में मनाया गया। तब से, यह गैंडों के संरक्षण के लिए समर्पित एक वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम बन गया है।**
- **इस पहल का नेतृत्व दो महिला संरक्षणवादियों - ज़िम्बाब्वे के चिशाकवे रैंच की लिसा जेन कैंपबेल और अमेरिका के सेविंग राइनोज़ की रिश्जा कोटा-लार्सन - ने किया, जिन्होंने इस वैश्विक आंदोलन को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।**
- **गैंडों की केवल पाँच प्रजातियाँ ही जीवित बची हैं: अफ्रीका में काले और सफेद गैंडे, और एशिया में भारतीय (बड़े एक सींग वाले), जावन और सुमात्रा गैंडे। जावन गैंडा गंभीर रूप से संकटग्रस्त बना हुआ है, जिसकी संख्या 70 से भी कम है।**

Key Points:-

(i) अंतर्राष्ट्रीय राइनो फाउंडेशन (IRF) की 2025 स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक गैंडों की आबादी लगभग 27,000 पर स्थिर हो गई है, और पिछले एक साल में इसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है।

(ii) भारत गैंडों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया के 80% से अधिक बड़े एक सींग वाले गैंडों की आबादी रहती है, जो विशेष रूप से असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में केंद्रित है।

3. विश्व कार-मुक्त दिवस 2025: सतत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 22 सितंबर को मनाया गया।

विश्व कार-मुक्त दिवस, जो 22 सितम्बर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, लोगों को वायु प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक दिन के लिए कारों का उपयोग न करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

- **यह अवधारणा 1973 के तेल संकट के दौरान शुरू हुई और 1994 में टोलेडो, स्पेन में आयोजित "सुलभ शहर" सम्मेलन के बाद इसमें तेजी आई, जिसके परिणामस्वरूप 1995 में विश्व कार मुक्त दिवस कंसोर्टियम का गठन हुआ।**
- **ब्रिटेन ने 1997 में पर्यावरण परिवहन संघ (ETA) के माध्यम से पहला राष्ट्रीय स्तर का कार-मुक्त**

अभियान शुरू किया। यूरोप ने 1999 में यूरोपीय संघ के "इन टाउन विदाउट माई कार" अभियान के तहत पहला अंतर्राष्ट्रीय कार-मुक्त दिवस मनाया, जो आगे चलकर यूरोपीय गतिशीलता सप्ताह (16-22 सितंबर) के रूप में मनाया गया।

• 22 सितम्बर को यूरोपीय संघ द्वारा प्रायोजित यूरोपीय मोबिलिटी सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें टिकाऊ गतिशीलता और वाहन प्रदूषण के प्रति जागरूकता पर जोर दिया जाएगा।

Key Points:-

(i) वैश्विक स्तर पर, परिवहन ग्रीनहाउस गैसों का एक प्रमुख योगदानकर्ता है, 1.47 बिलियन कारें ~3.5 गीगाटन (Gt) CO2/वर्ष उत्सर्जित करती हैं, जो जीवाश्म ईंधन CO2 का लगभग 10% और कुल GHG का 20% है।

(ii) सड़क वाहन प्रतिवर्ष लगभग 1.19 मिलियन मृत्यु और 50 मिलियन चोटों का कारण बनते हैं, जो कार पर निर्भरता को कम करने की आवश्यकता को उजागर करता है।

(iii) तीसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क वाले भारत में 21 करोड़ दोपहिया और 7 करोड़ चार पहिया वाहन हैं। 2030 तक वार्षिक कार बिक्री 4.5 मिलियन से बढ़कर 10.5 मिलियन होने का अनुमान है, जो भारत के कुल ग्रीनहाउस गैसों (~290 गीगाग्राम PM2.5/वर्ष) का 8% योगदान देगा।

DEFENCE

1. भारत ने LAC पर युद्ध की तैयारी बढ़ाने के लिए 'ज़ोरावर लाइट टैंक' का अनावरण किया।

सितंबर 2025 में, भारत ने DRDO, L&T और CVRDE द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत विकसित 'ज़ोरावर लाइट टैंक' का अनावरण किया, ताकि LAC पर भारतीय सेना को मज़बूत किया जा सके। जनरल ज़ोरावर सिंह के नाम पर, इसे ऊँचाई वाले इलाकों में चीन के टाइप-15 का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

• ज़ोरावर लाइट टैंक की परिकल्पना और निर्माण 24 महीनों के भीतर L&T के आर्मर्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स, हजीरा, गुजरात में किया गया। इसका वज़न 25 टन है, इसमें 3 लोगों का चालक दल है, और यह रेगिस्तान, ऊबड़-खाबड़ इलाकों और 4,200 मीटर से ज़्यादा ऊँचाई वाले क्षेत्रों में बेहतरीन गतिशीलता के लिए उच्च शक्ति-से-भार अनुपात (~30 अश्वशक्ति/टन) प्रदान करता है।

• कमिंस VTA903E-T760, 760 hp डीजल इंजन द्वारा संचालित, इस टैंक में RENK HMT-800 ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया है। यह 70 किमी/घंटा तक की गति प्राप्त कर सकता है और सड़क पर 70 किमी की परिचालन सीमा के साथ, समग्र रबर ट्रैक, हाइड्रो-न्यूमैटिक सस्पेंशन और अनुकूलनशीलता के लिए मॉड्यूलर कवच द्वारा समर्थित है।

• इस टैंक को सी-17 ग्लोबमास्टर III और चिनूक हेलीकॉप्टर जैसे भारी-भरकम विमानों के माध्यम से तेजी से तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है,

जिससे भारत की पर्वतीय सीमाओं पर तेजी से सेना जुटाने की क्षमता बढ़ जाएगी।

Key Points:-

(i) 105 मिमी मुख्य तोप, 7.62 मिमी समाक्षीय MG और 12.7 मिमी रिमोट-नियंत्रित स्टेशन से लैस, यह टैंक तीसरी पीढ़ी की फायर-एंड-फॉरगेट प्रणालियों सहित एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों (ATGM) को भी सपोर्ट करता है। सुरक्षा विशेषताओं में एक मॉड्यूलर कम्पोजिट आर्मर सिस्टम, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम (APS), लो इन्फ्रारेड सिग्नेचर और लेज़र वार्निंग रिसीवर शामिल हैं।

(ii) यह टैंक भारत की अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी को एकीकृत करता है, जिसमें स्थितिजन्य जागरूकता प्रणाली, सहायक बिजली इकाइयां और चुनौतीपूर्ण इलाकों के लिए उच्च ऊंचाई वाले हथियारों के साथ तीसरी पीढ़ी की ATGM संगतता शामिल है।

(iii) इस प्रोटोटाइप का लद्दाख के न्योमा में 4,200 मीटर से ऊपर रेगिस्तानी इलाके, उच्च ऊंचाई पर फायरिंग और गतिशीलता परीक्षणों सहित सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। भारतीय सेना में इसे पूर्ण रूप से शामिल करने का लक्ष्य 2027 तक है, और भविष्य में बेड़े के विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन की योजना है।

Static GK

Arunachal Pradesh (AR)	मुख्यमंत्री (CM) : पेमा खांडू	राज्यपाल : लेफ्टिनेंट (लेफ्टिनेंट) जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक (सेवानिवृत्त)
Comptroller and Auditor General of India (CAG)	सीएजी : के. संजय मूर्ति	स्थापना : 1858
RBI	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा	मुख्यालय: मुंबई
Union of European Football Associations (UEFA)	राष्ट्रपति : एलेक्ज़ेंडर चेफ़रिन	मुख्यालय : न्योन, स्विट्ज़रलैंड
Coal India Limited (CIL)	स्थापना: 1975	मुख्यालय: कोलकाता
Karnataka	मुख्यमंत्री: सिद्धारमैया	राज्यपाल: थावर चंद गहलोत
Larsen & Toubro Limited (L&T)	CEO & MD : शेखरीपुरम नारायणन सुब्रह्मण्यन	मुख्यालय: मुंबई
International Rhino Foundation (IRF)	कार्यकारी निदेशक (ED) : नीना फासियोन	मुख्यालय : टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)